भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5500

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण

5500. श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कोयला खनन के लिए कितने किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है और उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों सहित राज्य-वार कुल कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा खनन परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे के प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में चालू कोयला खानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, झांसी, गोंडा-बहराइच, देवरिया और ओडिशा के बालासोर में कोयले के लिए भविष्य में कोई खनन परियोजनाएं शुरु की जानी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : उन किसानों की संख्या का उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों सहित राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है जिनकी भूमि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की गई है :-

बीसीसीएल

बीसीसीएल में, पिछले 5 वर्षों (2021-22 तक) के दौरान कोयला खनन के लिए अधिग्रहित भूमि की मात्रा निम्नानुसार है: -

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत - शून्य

सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 - शून्य

सीधी खरीद - 166.76 एकड़ (झारखंड और पश्चिम बंगाल)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)

वर्ष	ईसीएल द्वारा अधिगृहित भूमि (हे.)	
	झारखंड	पश्चिम बंगाल
2017-18	19.12	107.61
2018-19	12.96	134.34
2019-20	124.28	55.47
2020-21	6	130.68
2021-22	627.11	176.1

भूमि के अधिग्रहण के दौरान, अधिकांश मामलों में भूमि का स्वामित्व निश्चित नहीं किया जाता है। यह प्रभावित परिवारों, जिनसे भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, को मुआवजे के भुगतान और/ या पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) लाभ प्रदान करने के दौरान निश्चित किया जाता है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

सीसीएल में, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है / अधिग्रहण किया जा रहा है। झारखंड में सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 73967 हेक्टेयर है। किसानों की कुल संख्या निश्चित नहीं की गई है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)

पिछले 05 वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 में फरवरी 2023 तक) के लिए, अधिग्रहित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना	राज्य	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 2013 की धारा - 9 के तहत भूमि के अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहित की गई कुल भुमि	कुल अधिग्रहित भूमि में से काश्तकारी भूमि का क्षेत्रफल	उन किसानों की सं. जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है
ब्लॉक-बी	मध्य प्रदेश	18-03-2021	395.96 हे.	63.50 हे.	660

निगाही	मध्य प्रदेश	24-11-2021	564.232 हे.	188.00 हे.	निश्चित नहीं किया गया

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)

राज्य	वर्ष	पिछले 5 वर्षों के दौरान जिन किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनकी संख्या (लगभग सं.)	अधिग्रहित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
महाराष्ट्र	2017-18	118	115.090
	2018-19	15	17.050
	2019-20	74	69.150
	2020-21	1010	1011.610
	2021-22	614	482.700

राज्य	वर्ष	पिछले 5 वर्षों के दौरान जिन किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनकी संख्या (लगभग सं.)	अधिग्रहीत की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
मध्य प्रदेश	2017-18	शून्य	शून्य
	2018-19	शून्य	शून्य
	2019-20	1	2.419
	2020-21	शून्य	शून्य
	2021-22	259	208.824

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)

पिछले 5 वर्षों (2017-18 से 2021-22 तक) के दौरान एसईसीएल द्वारा कोयला खनन के लिए जिन किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनकी संख्या और अधिग्रहित भूमि के कुल क्षेत्रफल का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	किसानों की संख्या	अधिग्रहित की गई कुल भूमि (टीएल/जीएल/एफएल) हेक्टेयर में
छत्तीसगढ़	8835 (लगभग)	2990.850
मध्य प्रदेश	939 (लगभग)	707.424

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)

पिछले 05 वर्षों के दौरान, एमसीएल ने केवल ओडिशा के अंगुल जिले में ही भूमि का अधिग्रहण किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	परियोजना	किसानो की संख्या	अधिग्रहित की गई कुल भूमि (टीएल/जीएल/एफएल) हेक्टेयर में
अंगुल	कनीहा	84	2.5 हे.
अंगुल	सुभद्रा	सर्वेक्षण प्रगति पर	126.58

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	अधिग्रहित की गई भूमि - एसीएस जीटीएस में।	उन किसानों की संख्या जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था
तेलंगाना	4120-14	3378

(ख) : सीआईएल की सहायक कंपनियां अधिकांशत: सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण करती हैं और मुआवजे का भुगतान, एमसीएल को छोड़कर जो ओडिशा आर एंड आर नीति, 2006 का पालन करता है, सीआईएल की मौजूदा आरएंडआर नीति/राज्य मानदंडों के अनुसार किया जाता था।

संबंधित अधिग्रहण अधिनियम और आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 के साथ पठित सीआईएल की आर एंड आर नीति, 2012 के प्रावधानों के अनुसार भूस्वामी भूमि मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

आर एंड आर के प्रावधान : सीआईएल की सहायक कंपनियां सीआईएल की मौजूदा आर एंड आर नीति और राज्य मानदंडों के अनुसार आर एंड आर लाभ प्रदान करती आ रही हैं। आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 के अनुसार, सीआईएल की सहायक कंपनियां सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 के तहत या मौजूदा राज्य मानदंडों के रूप में अधिग्रहित भूमि के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के अनुसार आर एंड आर लाभ प्रदान कर रही हैं।

इसके अलावा, सहायक कंपनियों के बोर्डों को संबंधित सहायक कंपनियों में मौजूदा विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में आर एंड आर नीति में आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है क्योंकि सीआईएल की आर एंड आर नीति 2012 व्यापक नहीं है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया था।

(ग) : उत्तर प्रदेश में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की प्रचालनरत खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

उत्तर प्रदेश में ककरी परियोजना और कृष्णाशिला परियोजना चालू हैं। बीना परियोजना, खड़िया परियोजना और दुधिचुआ परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आंशिक रूप से फैली हुई भूमि पर चालू हैं।

(घ) और (ड.) : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, झांसी, गोंडा-बहराइच, देवरिया और ओडिशा के बालासोर में कोयले के लिए सीआईएल की कोई भावी खनन परियोजना शुरू नहीं की जानी है।

****